



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 575]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 1980/पौष 1, 1902

No. 575]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 1980/PAUSA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1980

क्र० अ० 982(अ)/18 व ख/आईडीआर/80.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और नियन्त्रण) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 व ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० क्र० आ० 826 (अ)/18 व ख/आईडीआर/76, तारीख 23 दिसम्बर, 1976 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश रद्द किया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के अन्तर्गत होने की तारीख से छह पूर्व प्रवृत्त सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति, हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पत्राचारों, रणनीति आदेशों या अन्य लिखितों (महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत स्पष्ट नकद प्रत्यय सीमा के अधीन परादेश रकम के विस्तार तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रति दायित्वों को और नकद प्रत्यय लेखा (माधारण) में से मिल द्वारा निकाली गई रकमों को, जहाँ तक कि वे वर्तमान प्राप्तियों के अन्तर्गत हैं, छोड़कर) का प्रयत्न, जितना नैसर्गिक पुनर्गांव काष्ठन मिला विमिटेड, पुनर्गांव नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकने हों, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निरन्तर रोकेंगे और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाधनाएं और शक्तियां उक्त अवधि के लिए निरन्तर रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर विस्तारित की जाती रही है, जिसमें से अन्तिम विस्तारण 22 दिसम्बर, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए था;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि तीन मास के लिए और विस्तारित कर दी जानी चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और नियन्त्रण) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 व ख की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश को अवधि 22 मार्च, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए और विस्तारित करती है।

[क्र० सं० 3(17)/75-सीयूएस]

जी० वी० रामाकृष्णा, प्रतिनिधित्व सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 1980

S.O. 982(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18FB/IDRA/76 dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section

(1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than the liabilities to the State Bank of India to the extent of the amount outstanding on the clean cash credit limit guaranteed by the Government of Maharashtra and the amounts drawn by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets) to which the industrial undertaking known as Messrs. Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time, the last of such extensions being upto and inclusive of the 22nd December, 1980 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of three months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 22nd March, 1981.

[File No. 3(17)/75-CUS]

G. V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.